गुरुवार, 9 जुलाई,2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

जैकब बैथल ने लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

सोमवार टेस्ट में क्रैश आलिया भट्ट की अल्फा

Page-05

विपक्ष ने इसे "शीशमहल" कहकर सरकार पर निशाना साधा था, जबकि तत्कालीन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज किया था। अब नई सरकार इस भवन को सार्वजनिक उपयोग में लाकर विवादों से अलग नई पहचान देने की कोशिश में जुटी है।

'शीशमहल' बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस

आम लोगों के लिए भी खुल सकते हैं दरवाजे

दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक विवादों के केंद्र में रहा फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर-6 एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रूप में पहचान बना चुके इस बंगले को अब दिल्ली सरकार एक भव्य स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD) और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। यदि योजना को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो इस भवन का उपयोग देश-विदेश से आने वाले गणमान्य अतिथियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और विशेष प्रतिनिधिमंडलों के ठहरने के लिए किया जाएगा।सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से खाली पड़े इस आलीशान परिसर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि राजधानी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक उच्चस्तरीय राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और यह परिसर उस जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, भवन के कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए भी सीमित समय पर खोले जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ताकि लोग इसकी वास्तुकला और सरकारी धरोहर के रूप में इसे देख सकें।गौरतलब है कि यह बंगला अपने निर्माण, विस्तार और साज-सज्जा पर हुए खर्च को लेकर काफी समय तक राजनीतिक विवादों का विषय रहा। विपक्ष ने इसे "शीशमहल" कहकर सरकार पर निशाना साधा था, जबकि तत्कालीन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज किया था। अब नई सरकार इस भवन को सार्वजनिक उपयोग में लाकर विवादों से अलग नई पहचान देने की कोशिश में जुटी है। अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

- इस बंगले को अब दिल्ली सरकार एक भव्य स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है।
- इस भवन का उपयोग देश-विदेश से आने वाले गणमान्य अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के लिए किया जाएगा।

दिल्ली में शुरू होगी 'महिला समृद्धि योजना', हर महीने मिलेंगे ₹2,500

दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। सरकार की प्रस्तावित 'महिला समृद्धि योजना' के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस योजना की औपचारिक शुरुआत आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार की आय में सहयोग प्रदान करना है।बताया जा रहा है कि योजना का शुभारंभ एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। दिल्ली सरकार और संबंधित विभाग योजना के अंतिम दिशा-निर्देश तैयार करने में जुटे हैं। लाभार्थियों के चयन के लिए आय, निवास और अन्य पात्रता मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। साथ ही यह पहल महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विपक्ष ने हालांकि योजना के समय को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित बताया है।

शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता

A+++ श्रेणी का लश्कर कमांडर जाकिर गनी ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर के मीमंदर और सैदापोरा क्षेत्र के घने बागानों में पिछले पांच दिनों से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के ए+++ श्रेणी के कमांडर जाकिर गनी को मार गिराया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जाकिर गनी लंबे समय से घाटी में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था और कई हमलों की साजिश में उसकी भूमिका सामने आई थी। वह सुरक्षा बलों की मोस्ट वॉन्टेड सूची में शामिल था और उसके सिर पर इनाम भी घोषित किया गया था।यह अभियान भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (RR), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक सूचना के आधार पर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ कई घंटों तक चली। जवाबी कार्रवाई में जाकिर गनी मारा गया।सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इलाके में लश्कर का एक अन्य सक्रिय आतंकी लतीफ अब भी छिपा हो सकता है। इसी कारण पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। सेना ने अतिरिक्त जवानों और ड्रोन की मदद से जंगलों तथा बागानों की निगरानी बढ़ा दी है ताकि कोई आतंकी बचकर न निकल सके।अधिकारियों का कहना है कि इस सफलता से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अभियान के पूरी तरह समाप्त होने तक तलाशी जारी रहेगी।

ट्रंप के बयान के बाद सेंसेक्स 1900 अंक टूटा

पूर्व ओलंपियन और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2026 एशियाई खेलों के लिए कुश्ती चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के बाद सीधे जींद स्थित अपने जुलाना विधानसभा क्षेत्र पहुंचीं। वहां उन्होंने मीडिया से कई अहम मुद्दों पर बात की। हरियाणा में शुरू हो रहे एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "हरियाणा में एसआईआर की शुरुआत हो रही है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी फर्जी वोटर का नाम लिस्ट में शामिल न हो और जो असली वोटर्स हैं, उन्हें सूची से बाहर न किया जाए।" अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और गुटबाजी की खबरों पर विनेश फोगाट ने स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, "पार्टी के अंदर ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की तरह है। अगर हमारे अपने परिवार में कोई छोटी-मोटी नाराजगी होती भी है, तो हम उसे आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। मैं क्षेत्र में सभी को साथ लेकर चल रही हूँ और हर बात की जानकारी दे रही हूं।" उन्होंने आगे कहा, "इस समय कांग्रेस पार्टी का जोश बहुत हाई है। सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि हमें लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है, न कि किसी एक व्यक्ति से।" राजनीति और खेल के तालमेल पर बात करते हुए विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, "अगर राजनीति हमारे खेल को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, तो हमें भी राजनीति के मैदान पर उतरकर ध्यान देना होगा। मैं इस क्षेत्र में इसीलिए आई हूं ताकि अपने स्तर पर देश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और उन्हें सही मंच दिला सकूं।"

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा विवाद पर धामी सरकार सख्त

हाई लेवल जांच समिति गठित, आरोपी कर्मचारी निलंबित

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में चढ़ावे और दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गब्र्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप करेंगे। समिति में नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय में निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान को भी सदस्य बनाया गया है।सरकार ने जांच पूरी होने तक संबंधित आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि समिति मंदिर में दान राशि की प्राप्ति, गिनती, रिकॉर्ड संधारण और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं वित्तीय प्रबंधन या निगरानी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रही।समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदरीनाथ धाम हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहता है। ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़ी किसी भी अनियमितता की खबर सामने आने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच समिति का गठन किया है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाया जाएगा।

भाजपा के खिलाफ जिला स्तर तक चलेगा 'राम रक्षा आंदोलन'

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के मुद्दे ने अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ व्यापक राजनीतिक अभियान छेड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ठाकरे ने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को निर्देश दिया है कि "राम रक्षा आंदोलन" को केवल मुंबई तक सीमित न रखकर महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जाए।मंगलवार देर शाम मुंबई स्थित 'मातोश्री' में आयोजित रणनीतिक बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, जनसभाएं आयोजित करेंगे और लोगों के बीच जाकर मंदिर में दान राशि की सुरक्षा तथा पारदर्शिता का मुद्दा उठाएंगे। पार्टी का कहना है कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे की एक-एक राशि का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान में वित्तीय पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

अमेरिका के नए हमलों से पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव,ईरान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

इस बीच संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि मौजूदा तनाव यदि और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। बुधवार को अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े ठिकानों पर नए सैन्य हमले किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया और निवेशकों में चिंता बढ़ गई।अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में उसके सैन्य हितों और सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार तनाव बढ़ाने वाली नीतियां अपना रहा है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों की ओर से अभी तक पूर्ण युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं।इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। हमलों की खबर सामने आने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहा तो अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से होरमुज़ जलडमरूमध्य के आसपास किसी भी प्रकार की अस्थिरता पूरी दुनिया के ऊर्जा व्यापार को प्रभावित कर सकती है।तेल की कीमतों में तेजी का असर एशियाई शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला। भारत सहित कई प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल के महंगा होने से आयातक देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय मानी जा रही है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें विनिर्माण लागत और परिवहन खर्च को भी प्रभावित करती हैं।इस बीच संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि मौजूदा तनाव यदि और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कई देशों ने कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने पर जोर दिया है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और किसी बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका टाली जा सके।फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि तनाव कम नहीं हुआ तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं, संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अंकारा में हुई NATO समिट में डेनमार्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नई मांग को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इस समिट में गठबंधन के नेताओं ने ईरान पर अमेरिकी हमलों, रक्षा खर्च को लेकर दबाव और यूक्रेन के NATO में शामिल होने की कोशिशों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और सहयोगियों से आत्म-निर्णय और संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया। वहीं, NATO महासचिव मार्क रुटे ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की हालिया कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि सहयोगियों से ज़्यादा रक्षा खर्च की मांग करना वाशिंगटन का सही कदम था। यह बैठक यूरोप में अमेरिकी सेना की भूमिका को लेकर उठ रहे नए सवालों और ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के बीच होने वाली बातचीत से ठीक पहले हुई है। फ्रेडरिकसेन ने कहा कि ग्रीनलैंड ज़ाहिर है कि बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने आगे कहा हमें उम्मीद है कि सभी सहयोगी देश ग्रीनलैंड के लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार का सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा हम संप्रभु देश हैं और हम चाहते हैं कि सभी हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ट्रम्प ने यह मुद्दा फिर से उठाया कि अमेरिका को इस अर्ध-स्वायत्त द्वीप पर नियंत्रण रखना चाहिए, जबकि NATO का मूल सिद्धांत यह है कि इसके सदस्य देश एक-दूसरे के क्षेत्र की रक्षा करेंगे, न कि उस पर कब्ज़ा करने की धमकी देंगे।

यूएससी की अस्थाई सदस्यता का मास्टर प्लान जयशंकर तोड़ेंगेओआईसी का चक्रव्यूह!

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

एक तरफ भारत की बढ़ती वैश्विक धमक है तो दूसरी तरफ 57 इस्लामिक देशों का वो ताकतवर ब्लॉक जिसे ओआईसी कहा जाता है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐसी जंग की बिसात बीच चुकी है जो आने वाले दशकों के लिए वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 जुलाई को न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके बैग में सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि भारत की 2028-29 के लिए यूएससी की अस्थाई सदस्यता का वो मास्टर प्लान है जिसे दुनिया के कई देश बचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल भारत अपनी दावेदारी उस वक्त पेश कर रहा है जब दुनिया एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। यूक्रेन युद्ध थमा नहीं था कि मिडिल ईस्ट में आग लग गई। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के दबाव ने पूरे ग्लोबल साउथ को हिलाकर रख दिया। आज विकासशील देश खाद्य और ईंधन के संकट से करा रहे हैं। भारत यहां एक मसीहा के रूप में उभर रहा है और डॉक्टर एस जयशंकर का तर्क सीधा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था अपनी प्रासंगिकता खो देगी। लेकिन सुधारों की इस मांग के बीच असली खेला शुरू हुआ है एशिया पेसिफिक की उस एक सीट के लिए जिस पर भारत और तजाकिस्तान दोनों की नजरें हैं। अब बात करते हैं उस अड़ंगे की जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस अड़ंगे का नाम है तजाकिस्तान और ओआईसी का चक्रव्यूह। इसका सीधा मतलब 57 वोट एक मुस्त तजाकिस्तान की झोली में यहां एक कूटनीतिक पेच समझिए। भारत और तजाकिस्तान दोनों ही एसइओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। किरगिस्तान में होने वाली आगामी एससीओ समिट अब एक अखाड़ा बनने वाली है।

बलूचिस्तान में हवाई बमबारी और ड्रोन हमला नागरिकों की संपत्ति का हुआ नुकसान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों में बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुजदार और मस्तंग जैसे जिलों में हुई घटनाओं ने पाकिस्तानी सेना और सरकारी सुरक्षा अभियानों के खिलाफ व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए। ध्यान रहे कि बलूच यकजेहती कमेटी ने जनता की मांगों को लेकर 3 जून को मस्तुंग के दश्त कुम्बैल इलाके में हड़ताल की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला मोहम्मद इब्राहीम नाम के एक निवासी के घर पर हुआ। संगठन का दावा है कि परिवार के 50 से अधिक पालतू जानवर मारे गए। बीवाईसी ने कहा कि ये जानवर परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। हमलों में रिहाइशी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप

से घायल हुए हैं। खुजदार समेत प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू लगा रहा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संचार पर लगी इन पाबंदियों के कारण बिना किसी सजा के अत्याचार होते रहते हैं और मरने वालों की तादाद की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है। रीजन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन हमलों में भी तेजी आई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति और नागरिकों को अतिरिक्त नुकसान पहुंचा है।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर फिर से ग्रहण

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर फिर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। होर्मुज में ईरान के तीन शिप पर किए गए हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सख्त लहजे में कहा, ईरान के साथ सीज़फायर डील "खत्म" हो गई है। तुर्की में NATO समिट के दौरान ट्रंप ने कहा, "मेरे लिए, यह समझौता खत्म हो चुका है। मैं अब उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता। वे घटिया लोग हैं और अगर उन्हें न्यूक्लियर हथियार मिल जाता है... वे झूठे हैं... मेरी नज़र में, उनसे बात करते रहना समय की बर्बादी है। वे पागल हैं, मेरे लिए यह सब खत्म हो चुका है।" ईरान के ख़ातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि अगर ईरानी संप्रभुता के ख़िलाफ़ आक्रामकता के मामले में अमेरिकी सेना को कहीं से भी मदद मिलती है, तो उस मदद के स्रोत को देश की सेना एक वैध निशाना मानेगी। अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के एक बयान में, ईरान की सेना की एक कमांड यूनिट, हेडक्वार्टर ने कहा: "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की संप्रभुता और क्षेत्र के ख़िलाफ़ आक्रामक अमेरिकी सेना को मिलने वाली किसी भी मदद के स्रोत को सेना एक वैध निशाना मानेगी और उस देश को इसका अंजाम भुगतना होगा।" बता दें कि बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तब और बढ़

गया जब अमेरिका ने नए हमले किए और तेहरान ने 'करारा' जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान की संसद के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, अमेरिका को "होर्मुज़ में ईरान की नई व्यवस्था को मान्यता देनी चाहिए"। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अज़ीज़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर यह टिप्पणी की। उन्होंने यह बात रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की उस घोषणा के जवाब में कही, जिसे उन्होंने अमेरिका के हमले के खिलाफ़ "शुरुआती प्रतिक्रिया" बताया था। उन्होंने कहा, "इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हर हाल में अमेरिका को होर्मुज़ में ईरान की नई व्यवस्था को मान्यता देनी चाहिए।" ईरान के अधिकारियों का कहना है कि रात भर हुए अमेरिकी हमलों में खुज़ेस्तान प्रांत के कई इलाके प्रभावित हुए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए।तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इन हमलों में दक्षिण-पश्चिमी प्रांत के माहशहर, इमाम खुमैनी पोर्ट और हमिदिया शहरों में कई जगहों को निशाना बनाया गया।

संपादक की कलम से

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमेशा से पड़ता रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर देश की ऊर्जा लागत, महंगाई और आम नागरिकों की जेब पर प्रभाव डालता है। पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं आई। इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब तेल सस्ता हो रहा है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही।यह प्रश्न केवल राजनीति का नहीं, बल्कि आर्थिक नीति और जनहित का भी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल कच्चे तेल के भाव से तय नहीं होतीं। इनमें रिफाइनिंग लागत, परिवहन, विपणन खर्च, केंद्र और राज्य सरकारों के कर तथा विनिमय दर जैसे कई कारक शामिल होते हैं। इसके बावजूद यह भी उतना ही सत्य है कि आम नागरिक इन तकनीकी पहलुओं से अधिक अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को महसूस करता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हुआ है तो घरेलू बाजार में भी उसका लाभ दिखाई देना चाहिए।महंगाई आज भी देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्यान्न, फल-सब्जियों, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की लगभग हर वस्तु महंगी हो जाती है। इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और किसानों पर पड़ता है। ऐसे में यदि ईंधन की कीमतों में थोड़ी भी राहत मिलती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है।सरकार का पक्ष भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें स्थिर नहीं रहतीं। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती जैसे कारण कभी भी कीमतों को फिर ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे में सरकार कई बार भविष्य के जोखिमों को देखते हुए तत्काल कीमतों में कटौती करने से बचती है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला कर राजस्व सरकार की विकास योजनाओं और सार्वजनिक व्यय का भी महत्वपूर्ण स्रोत है।फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि सरकार कीमतों में कटौती नहीं कर सकती, तो उसे इसके आर्थिक कारण स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने चाहिए। इससे अनावश्यक राजनीतिक विवाद कम होंगे और नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। दूसरी ओर विपक्ष की जिम्मेदारी भी केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान भी प्रस्तुत करने चाहिए। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में ऊर्जा मूल्य निर्धारण की नीति केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन का प्रश्न है। सरकार को राजस्व और जनहित के बीच संतुलन बनाना होगा, जबकि विपक्ष को तथ्य आधारित आलोचना करनी होगी। अंततः किसी भी आर्थिक नीति की सफलता इसी में है कि उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे।

कच्चे तेल की कीमतों पर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला

बोले- जनता को सस्ता पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?

भाजपा की ओर से इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें केवल कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव पर निर्भर नहीं करतीं। इनमें रिफाइनिंग लागत, परिवहन, टैक्स, विनिमय दर और अन्य आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बुधवार को राजनीति तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद आम जनता को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं, लेकिन भारत में उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण ईंधन की ऊंची कीमतें हैं। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल महंगे रहने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका असर खाद्यान्न, सब्जियों, दूध और रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं तो उसका सीधा लाभ देश की जनता को भी मिलना चाहिए।सपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की बजाय तेल कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो देश में ईंधन महंगा करने में देर नहीं लगती, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो सरकार राहत देने से बचती है। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से सबसे अधिक प्रभावित गरीब, किसान और मध्यम वर्ग हो रहा है।भाजपा की ओर से इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें केवल कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव पर निर्भर नहीं करतीं। इनमें रिफाइनिंग लागत, परिवहन, टैक्स, विनिमय दर और अन्य आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है और विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रम से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए आगे की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।ईंधन की कीमतों को लेकर शुरू हुआ यह नया राजनीतिक विवाद ऐसे समय सामने आया है जब संसद का मानसून सत्र भी निकट है। माना जा रहा है कि विपक्ष महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के मुद्दे को संसद के भीतर भी जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी कर रहा है, जबकि सरकार आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक बाजार की स्थिति का हवाला देकर अपना पक्ष रखेगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल, जयंत पाटिल की भाजपा नेता से मुलाकात पर अटकलें तेज

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। इस बैठक के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों और संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से मुलाकात को सामान्य बताया गया, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके कई राजनीतिक मायने निकाले हैं।बैठक की जानकारी सामने आते ही यह अटकलें लगने लगीं कि क्या शरद पवार गुट भविष्य में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच इस मुलाकात ने चर्चाओं को और हवा दे दी। हालांकि एनसीपी (शरद पवार) के नेताओं ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी विपक्ष में है और उसकी राजनीतिक लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्षी दलों के बीच स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर अधिक टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि अलग-अलग दलों के नेताओं के बीच मुलाकात होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है और इसे राजनीतिक सौदेबाजी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बदलते गठबंधन और दल-बदल की राजनीति के कारण किसी भी बड़ी मुलाकात पर स्वाभाविक रूप से अटकलें लगने लगती हैं। ऐसे में जयंत पाटिल और विनोद तावड़े की मुलाकात ने भी राज्य की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।फिलहाल एनसीपी (शरद पवार) ने स्पष्ट किया है कि भाजपा के साथ जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बावजूद इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है और आने वाले दिनों में इस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।

भूपेंद्र यादव के कार्यालय से चार अधिकारियों को हटाने पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से चार अधिकारियों को हटाए जाने के फैसले ने बुधवार को राजनीतिक रंग ले लिया। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था का संकेत बताया। पार्टी का आरोप है कि यदि किसी केंद्रीय मंत्री के कार्यालय में एक साथ इतने अधिकारियों को हटाने की नौबत आती है, तो सरकार को इसके पीछे की वजह देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह केवल एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में निर्णय प्रक्रिया और समन्वय को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार पूरे मामले पर पारदर्शिता बरते और बताए कि आखिर किन परिस्थितियों में यह कार्रवाई की गई। पार्टी का कहना है कि प्रशासनिक जवाबदेही लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस तरह के मामलों में स्पष्ट जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है।वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और कार्यमुक्त करना सरकार की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी राजनीतिक विवाद से जोड़ना उचित नहीं है। पार्टी का कहना है कि मंत्रालयों में कार्यकुशलता बढ़ाने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं।भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हर प्रशासनिक फैसले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। सरकार का कहना है कि सभी निर्णय निर्धारित नियमों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप लिए गए हैं।इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर सरकार से जवाब मांग सकता है। दूसरी ओर भाजपा इसे पूरी तरह प्रशासनिक विषय बताते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दे रही है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया आने की संभावना है।

NEET के बाद अब यूजीसी-नेट पर सवाल

पेपर लीक के आरोपों से शिक्षा व्यवस्था कठघरे में

पेपर लीक का सिलसिला थमने के नाम नहीं ले रहा है। पिछले दो महीने में लगातार कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। NEET, महाराष्ट्र TET, हरियाणा टीईटी के बाद, अब नेशनल लेवल एग्जाम यूजीसी नेट पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में यूजीसी नेट के सवाल लीक होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक परीक्षा में सेंधमारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। यूजीसी नेट को लेकर दावा किया जा रहा है कि 30 जून 2026 को हुई सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा का पेपर पहले लीक हो गया था। एक 100 पेज PDF सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि पीडीएफ के लगभग 90 सवाल परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मेल खा रहे हैं। खुद के यूजीसी नेट एस्पिरेंट बतानी वाली एक छात्रा ने कहा कि उसने इस बार सोशियोलॉजी का पेपर दिया था और यह पक्का कर सकती है कि यह वही क्वेश्चन पेपर है जिसके लिए एग्जाम दिया था। छात्रा ने एक्स पर लिखा, 'एक कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम का हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक एग्जाम के ठीक एक हफ्ते बाद ऑनलाइन घूम रहा है? अभी तक कोई आंसर की नहीं है, और फिर भी, इस डॉक्यूमेंट में सवाल बिल्कुल असली टेस्ट के फॉर्मेट जैसे ही हैं?'

नेट एस्पिरेंट ने आगे लिखा, 'सवालों से मैच करने वाले कोड तक, सारी डिटेल्स एक जैसी हैं। और वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था? कि NTA से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था? मैं यहां ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो NEET पेपर लीक मामले के बाद बहुत अच्छे क्रिटिक्स, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स ने पहले ही न कहा हो। लेकिन यह घटना अब मेरा खून भी नहीं खौलाती। बस मुझे, और लाखों स्टूडेंट्स को, उम्मीद से खाली कर देती है।' लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने UGC-NET परीक्षा में नई गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया गया था और उसमें दिए गए सवाल सोशियोलॉजी के पेपर में पूछे गए कई सवालों से मेल खाते थे। उन्होंने दावा किया कि यह पेपर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 2.25 लाख रुपये में बेचा जा रहा था। इसके अलावा, उसी नेटवर्क ने CSIR-NET, HTET और ADA जैसी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर परीक्षा के पेपर लीक होने के बार-बार आरोप लगने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। कथित यूजीसी नेट पेपर लीक पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने X पर कहा कि छात्रों को जवाबदेही और न्याय से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, 'पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है। न तो कोई जांच होगी और न ही छात्रों को न्याय मिलेगा।'

डीयू में पहले से दो साल के 74 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज हैं, इनके लिए करीब 13500 सीटें

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक साल के 46 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हैं। पहली बार डीयू में एक साल के पीजी कोर्स शुरू हो रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने डीयू से चार साल का अंडरग्रैजुएट कोर्स पूरा किया है। डीयू में पहले से दो साल के 74 पोस्टग्रैजुएट कोर्सेज हैं, इनके लिए करीब 13500 सीटें हैं। वहीं, एक साल के पीजी कोर्स 46 हैं, जिनकी सीटें 1100 से ज्यादा हैं यानी कुल मिलाकर इस साल 14600 सीटों पर दाखिले होंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जुलाई है। दो साल के पीजी के अलावा अब एक साल के 46 कोर्स शुरू होने के साथ-साथ डीयू के टीचर्स का वर्कलोड भी बढ़ेगा, डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ दिक्कतें आएंगी। हालांकि, डीयू के वाइस चांसलर प्रो योगेश सिंह का कहना है कि रूटीन चैलेंज तो होंगे मगर मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके लिए टाइमटेबल पर विभागों ने काम शुरू हो कर दिया है। अगर दिक्कतें या शिकायतें आती हैं, तो हम इस पर तुरंत काम करेंगे। उनका कहना है कि यह एक साल के पीजी का पहला साल है, इसे अच्छी तरह से शुरू किया जाएगा। वैसे हमारी पास फैकल्टी की कमी नहीं है, परमानेंट अपॉइंटमेंट के बाद पर्याप्त टीचर्स आ चुके हैं। दूसरी ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी धीरे-धीरे पूरी हो रही है। डीयू कंप्यूटर सेंटर की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, फैकल्टी ऑफ टेक्नलॉजी की बिल्डिंग दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। डीयू में NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) के तहत 2022 में चार साल का यूजी शुरू किया, जिसका पहला बैच इस साल पासआउट कर रहा है। करीब 20 हजार स्टूडेंट्स ने मेजर के साथ चार साल का यूजी पूरा किया है।

नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2026 के सेमीफाइनल में बनाई जगह

निशाने पर उमरान मलिक का रिकॉर्ड तेज गति से कभी समझौता नहीं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सीनियर पुरुष टीम के चयनकर्ताओं ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की 20टी इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की टीम की घोषणा की है। इस दौरे के लिए राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को भी चुना गया है। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के इस पेसर ने अपनी तेज रफ्तार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उसी का नतीजा है कि अब वह जिम्बाब्वे के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस सीरीज से पहले उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वह एक दिन 160 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह भारत के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर बन जाएंगे। अशोक शर्मा ने भारतीय टीम में चुने जाने को लेकर टीओआई को बताया कि टीम मैनेजमेट ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुझसे पासपोर्ट मांगा था, लेकिन उस सीरीज के लिए नहीं चुना गया। हालांकि मुझे पता था कि मुझे मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि इस साल बहुत सारा क्रिकेट खेला जाना है। अब 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पहली बार चुना गया है। बता दें कि अशोक शर्मा ने पिछले घरेलू सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और वह भारत के सबसे नए फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बन गए हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के लिए 22 विकेट लेकर 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए अपनी तेज रफ्तार से सेलेक्टर समेत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन को ''बेहद खराब'' करार दिया

भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से 125 रन की करारी हार के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन को "बेहद खराब" करार दिया और कहा कि इस तरह का प्रदर्शन कतई स्वीकार्य नहीं है। अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं जीता है। मंगलवार को खेले गए मैच में तो उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा जब टीम 202 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 11.4 ओवर में 76 रन पर आउट हो गई और उसे रन के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अय्यर ने मैच के बाद कहा, "यह बेहद निराशाजनक था, इतने बड़े अंतर से हारना स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले हमें हार को स्वीकार करना होगा और नए सिरे से रणनीति बनानी होगी।" इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। गुरुवार को ब्रिस्टल में चौथा टी20 मैच और शनिवार को साउथेम्प्टन में अंतिम मैच खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अय्यर का मानना था कि ट्रेंट ब्रिज की इस पिच पर गेंदबाजों को 200 रन नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह 200 विकेट वाली पिच थी। हमने पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए और इसी वजह से हम पिछड़ गए। आप कितनी भी योजना बना लें, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। मुझे लगा कि हार्ड लेंथ पर शॉट लगाना मुश्किल था और हम उसे ठीक से अंजाम नहीं दे पाए।" भारतीय कप्तान ने कहा, "हमें अब अतीत के बारे में नहीं सोचना होगा और मजबूत वापसी करनी होगी। हमारे प्रत्येक खिलाड़ी को इस पर विचार करना होगा कि वह किस तरह से योगदान दे सकता है।वापसी के रोडमैप पर बात करते हुए कप्तान ने टीम के सभी खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया है। अय्यर ने कहा, "हमें अब अतीत के इस बुरे प्रदर्शन को पीछे छोड़ना होगा और मजबूत मानसिक स्थिति के साथ वापसी करनी होगी।

जैकब बैथल ने लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली

आईसीसी रैंकिंग अपडेट कर दी गई है। इस बार बहुत ज्यादा उलटफेर और बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के ईशान किशन को हल्का सा फायदा रेटिंग में हुआ है। इस बीच इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जैकब बैथल ने लंबी छलांग लगाते हुए टॉप 10 में एंट्री मार दी है, वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे बाहर हो गए हैं। आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के बीच आईसीसी की ओर से नई टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन पहले नंबर की कुर्सी पर बने हुए हैं। उनकी रेटिंग बढ़कर अब 897 की हो गई है। एक जुलाई को ईशान की रेटिंग 876 की थी, जो अब ज्यादा हो गई है। हालांकि इससे कुछ ही दिन पहले तक उनकी रेटिंग 904 तक जा पहुंची थी, उससे रेटिंग कम हुई है। इस बीच भारत के ही दो बल्लेबाज पहले और दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। ईशान किशन तो पहले नंबर पर हैं ही, साथ ही अभिषेक शर्मा उनका पीछा कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा की मौजूदा रैंकिंग 881 की है। यानी इन दोनों टॉप बल्लेबाजों के बीच काफी कम अंतर है। इस बीच बड़ी बात ये है कि इंग्लैंड के जैकब बैथल आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी रेटिंग अब 708 की हो चुकी है। उन्हें एक साथ सात स्थानों का फायदा मिला है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, इसका असर उनकी रेटिंग पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सूर्या अब टॉप 10 से बाहर होकर सीधे 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें पांच स्थानों का नुकसान हुआ है। उनकी रेटिंग 687 की नजर आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त टी20 सीरीज खेली जा रही है। अभी दो और मैच बाकी हैं। सीरीज का चौथा मैच 9 जुलाई को खेला जाएगा, वहीं आखिरी मैच 11 जुलाई को है।

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अब स्टार बन चुकी हैं. रियलिटी शो लॉक अप में सुनीता ने अपने वन लाइनर्स और बेबाक अंदाज से तहलका मचा रखा है. सुनीता ने बिंदास एटीट्यूड के फैंस मुरीद हो गए हैं. शो में सुनीता अपनी शादी से जुड़े कई सीक्रेट रिवील कर रही हैं. अब उन्होंने एक बार फिर गोविंदा के अफेयर पर बात की. शो में शिल्पा शिंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री होते ही लॉक अप का पारा हाई हो गया है. शिल्पा खुल्लम-खुल्ला हर किसी से पंगे ले रही हैं.

चौथे दिन गिरा कलेक्शन, हिट होना मुश्किल

मंडे टेस्ट में क्रैश आलिया भट्ट की 'अल्फा'!

स्पाई-यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' मंडे टेस्ट में थोड़ी कमजोर साबित हुई है. दमदार वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट नजर आई, जो इस फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है. आने वाले दिन बॉक्स ऑफिस पर आलिया की फिल्म के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं.

आलिया भट्ट और शरवरी की स्पाई-यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' शुक्रवार को काफी चर्चाओं के साथ रिलीज हुई थी.

वीकेंड में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाती नजर आ रही थी, लेकिन सॉलिड वीकेंड कलेक्शन के बाद फिल्म का असली टेस्ट मंडे को होना था. अब मंडे के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ गए हैं, जो बताते हैं कि 'अल्फा' चौथे दिन से स्लो पड़ने लगी है. फिल्मों का बड़ा टेस्ट लेने वाले सोमवार को 'अल्फा' की कमाई में बड़ी गिरावट आई है. शुक्रवार को 9.25 करोड़ के ओपनिंग कलेक्शन के साथ एंट्री लेने वाली 'अल्फा', जनता को थिएटर्स तक खींचती नजर आई. शनिवार-रविवार की कमाई एक अच्छे जंप के साथ डबल डिजिट्स में पहुंची, इसलिए वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन 34 करोड़ तक पहुंच गया था. अब सैकनिल्क का डेटा बताता है कि 'अल्फा' ने चौथे दिन यानी सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.85 करोड़ नेट कलेक्शन किया है. संडे की कमाई 13.25 करोड़ के मुकाबले मंडे की गिरावट 70% से ज्यादा है.

शादी से पहले 'प्लेबॉय' थे राम कपूर, लॉक अप में किया खुलासा

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में जाने-माने एक्टर राम कपूर ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में खुलकर बात करके साथी कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया. श्रेया कालरा के साथ एक हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान, एक्टर ने अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताया और एक्ट्रेस गौतमी कपूर से शादी से पहले प्रोड्यूसर एकता कपूर से जुड़ी एक मजेदार घटना भी शेयर की.

ही एक ठगी का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित बनकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली मिस्र की

उन्हें कभी कैंसर था ही नहीं. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनिया फोद सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर करती थीं, जिनमें वह खुद को

महंगी लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे. डोनिया फोद डोनेशन में मिले पैसों से उन्होंने कार खरीदी, फ्लैट लिया और कई लग्जरी

रिपोर्ट में न कीमोथेरेपी का जिक्र था और न ही रेडिएशन का. बताया गया कि डोनिया को सिर्फ कुछ सामान्य स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें थीं, जिनका इलाज चल रहा था.

अनुमानित और अव्यवस्थित, लेकिन कुछ कमी लगती थी भारत में ट्रैफिक है, प्रदूषण है, शोर है, भीड़ है, अनिश्चितता है... फिर भी यहां कुछ है जो वहां नहीं मिलता.

यूएई में बढ़ती गर्मी के बीच पुलिस का सख्त फैसला

कार में बच्चे को अकेला छोड़ा तो होगी जेल और भारी जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपने कड़े नियमों के लिए जाना जाता है. अब यहां बढ़ती गर्मी को लेकर भी एक नियम लागू किया गया है, जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है. दरअसल, यहां की पुलिस बढ़ती गर्मी को लेकर सख्त हो गई है और अब पुलिस की ओर से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो इस भयानकर गर्मी में बच्चों को अकेले कार में छोड़कर कहीं चले जाते हैं. शारजाह, अजमान, फुजेराह में पुलिस ने बच्चों को खड़ी गाड़ियों के अंदर बिना निगरानी के छोड़ने पर कार्रवाई करने की बात कही है. लीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभी वहां पारा 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंचने का

अनुमान है. इसलिए अधिकारी इस मौसमी खतरे को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं. कानून प्रवर्तन एजेंसियां भीषण गर्मी से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए गहन जागरुकता अभियान चला रही हैं. शारजाह पुलिस के यातायात के डायरेक्टर ब्रिगेडियर खालिद अल-काय ने इस बात पर जोर दिया.

वैज्ञानिकों ने बनाया फॉर्मूला, जो बताएगा प्रलय की तारीख!

इंसानों का कब धरती से होगा सफाया?

धरती पर इंसानों का अस्तित्व कब तक रहेगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान करते रहे हैं. समय-समय पर दुनिया के खत्म होने यानी प्रलय को लेकर कई भविष्यवाणियां भी सामने आती रही हैं. लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला पेश किया है, जो दावा करता है कि वह यह अनुमान लगा सकता है कि इंसान कब तक इस धरती पर रहेंगे. हालांकि यह कोई तय भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है. इसे 'डूम्सडे आर्ग्यूमेंट' यानी प्रलय तर्क कहा जाता है.

इस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिकों का

तर्क काफी दिलचस्प है. उनका अनुमान है कि मानव इतिहास में अब तक करीब 117 अरब लोग जन्म ले चुके हैं और इस धरती पर जीवन जी चुके हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जीवित इंसान मानव इतिहास की टाइमलाइन में किसी खास या शुरुआती स्थान पर नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल सामान्य और रैंडम जगह पर हैं. यहीं से गणित शुरू होता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अब तक जन्मे 117 अरब लोग मानव इतिहास के कुल लोगों का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा हैं, तो 100 प्रतिशत संख्या इससे 20 गुना ज्यादा होगी. इसी आधार पर 117 अरब को 20 से गुणा किया गया. इससे आंकड़ा निकलकर करीब 2.34 ट्रिलियन यानी 2 लाख 34 हजार करोड़ लोगों तक पहुंचता है.

'मुझे Kiss करो...' विदेशी टूरिस्ट को परेशान करता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर अक्सर विदेशियों से बदतमीजी करने के वीडियो सामने आते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो कोलकाता से सामने आया है, जिसमें एक भारतीय शख्स ऑस्ट्रेलियाई युवक को परेशान कर रहा है, जिसके बाद से भारतीय शख्स की आलोचना हो रही है. दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक भारतीय शख्स विदेशी टूरिस्ट को बार-बार किस करने के लिए कह रहा है. विदेशी ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर मार्को रोम्स ऐसा करने से मना भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय शख्स बार-बार ऐसा करने के लिए कहता नजर आ रहा है.

PAK में पीरियड टैक्स हटने से बदलेगी सूरत?

पाकिस्तान ने पीरियड टैक्स हटाने का फैसला लिया है. देश में सैनिटरी पैड और दूसरे मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स पर लगने वाला 'पीरियड टैक्स' खत्म करने की घोषणा की गई है. जानते हैं आखिर ये पीरियड टैक्स होता क्या है और इसके हटने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?

पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसका असर सीधे करोड़ों महिलाओं की जिंदगी पर पड़ सकता है. वहां एक एक मंत्री ने इसका ऐलान किया है. दरअसल, एक टैक्स की वजह से पाकिस्तान की करोड़ों महिलाएं पीरियड जैसे संवेदनशील समय में सैनेटरी पैड की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं. यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% महिलाएं ही बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर पाती हैं और बाकी ज्यादातर महिलाएं कपड़े या घरेलू विकल्पों के सहारे रहती हैं. ऐसे हालात यहां लागू पीरियड टैक्स की वजह से हैं. ऐसे में इस टैक्स को हटाने का फैसला बड़ी राहत दे सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीरियड टैक्स क्या है और इसके हटने से क्या वास्तव में हालात बदल जाएंगे?

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक,

कब आएगा बदलाव?

पाकिस्तान में पीरियड टैक्स हटाने का फैसला निश्चित रूप से एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे सैनिटरी उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं और लाखों महिलाओं के लिए इन्हें खरीदना आसान हो सकता है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली बदलाव तब आएगा, जब सस्ते सैनिटरी उत्पादों के साथ-साथ साफ पानी, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और पीरियड्स को लेकर समाज में फैली झिझक भी खत्म होगी.

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने घोषणा की है कि सैनिटरी पैड और महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े जरूरी उत्पादों पर लगने वाला सेल्स टैक्स हटाया जाएगा.

राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश-निशिकांत आमने-सामने

मानहानि नोटिस के बाद बढ़ा सियासी घमासान

विवाद बढ़ने पर मंगलवार को समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में आरोप लगाया गया कि बीजेपी सांसद जानबूझकर अखिलेश यादव और सपा के प्रति नफरत फैला रहे हैं और उनकी छवि खराब कर रहे हैं।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के गोड्डा से BJP के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। यह विवाद अब मानहानि के नोटिस तक पहुंच गया है जिसके बाद निशिकांत दुबे ने सपा प्रमुख पर करारा पलटवार किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में बिना अखिलेश यादव का नाम लिए टीपू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही राम मंदिर दान चोरी के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और टीपू के बीच आपसी कनेक्शन का दावा किया गया था। इस पोस्ट के बाद सपा नेताओं ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें 10 मिनट के भीतर पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद सपा नेता मनोज काका सहित कई अन्य नेताओं ने अलग-अलग जिलों में बीजेपी सांसद के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा था कि, 'अखिलेश जी इस तरह का वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है, मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा ना, कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाले कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए।' विवाद बढ़ने पर मंगलवार को समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में आरोप लगाया गया कि बीजेपी सांसद जानबूझकर अखिलेश यादव और सपा के प्रति नफरत फैला रहे हैं और उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें दो हफ्ते के भीतर माफी मांगने को कहा गया। मानहानि का नोटिस मिलने के बाद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश से 3 सवाल भी पुछे है। निशिकांत ने आज यानी बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि, 'मैंने अखिलेश यादव जी को फुसलाने वाले वकील को कानूनी जवाब कल ही भेज दिया, अखिलेश यादव जी कन्हैया पाल जी का क्या मानहानि हुआ यह हमने पूछा? दूसरा आपका नाम किस सरकारी दस्तावेज में टीपू है ? तीसरा आप और आपकी पार्टी के लोग अकारण मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं उसका कानूनी खर्च आपके वकील साहब से हर्जाना लूंगा।' टिन्नू यादव राम मंदिर दान चोरी मामले का मुख्य आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक उसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी और उनका पूर्व ड्राइवर रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि टिन्नू और अखिलेश यादव के बीच फोन पर सैकड़ों बार बातचीत हुई है। हालांकि एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ऐसे किसी भी संपर्क का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

नशे की हालत में नहर में गिरे व्यक्ति को बचाया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

पारा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक व्यक्ति नशे की हालत में थाने के सामने स्थित नहर में गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में से एक सिपाही रस्सी लेकर उसे बचाने कूद गया। सिपाही ने 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद दूसरे सिपाहियों ने उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। इस बचाव अभियान में एक पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल भी हो गया। जानकारी के अनुसार, देर रात एक युवक नहर के पास पहुंचा और नशे की हालत में अचानक नहर में गिर। युवक को नहर में गिरते देख आसपास मौजूद लोग चिल्लाने लगे। सूचना मिलते ही पारा थाने पर तैनात आरक्षी उदय भान और मनोज तुरंत मौके पर पहुंचे। उसी समय जोनल चेकिंग कर रहे उप निरीक्षक रविशंकर मौर्य और पुलिसकर्मी राजेश गुप्ता भी वहां पहुंच गए। पुलिस टीम ने बिना देरी किए बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद युवक को नहर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान कॉन्स्टेबल मनोज को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उनकी हालत सामान्य बताई गई है। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान शिव शंकर पुत्र दुलारे, निवासी डूडा कॉलोनी, हंसखेड़ा, थाना पारा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, वह शराब के नशे में था। उसे समझाने-बुझाने के बाद सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और घटना की पूरी जानकारी दी गई। पारा पुलिस की इस त्वरित और मानवीय कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सक्रियता नहीं दिखाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस अधिकारियों ने भी बचाव अभियान में शामिल जवानों की प्रशंसा की है।

26 घंटे की छापेमारी में खुला भ्रष्टाचार का खजाना, सोना-चांदी और नकदी बरामद

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर विजिलेंस ने छापा मारा। करीब 26 घंटे चली छापेमारी में ललित कुमार के लखनऊ आवास से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। तलाशी के दौरान टीम को करीब 1.62 करोड़ रुपए कैश भी मिला, जो उसने पैकेटों में दीवार और अलग-अलग कमरों में छिपाकर रखे थे। 15 जगहों पर मकान, फ्लैट और खेती की जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। विजिलेंस ने बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई है। आरोपी ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली में सेंगहो कोठी के रहने वाले हैं। विजिलेंस विभाग के अनुसार, ललित कुमार के खिलाफ 2024 में कानपुर में तैनाती के दौरान करप्शन की शिकायत की गई थी। उस वक्त वह आरटीओ ऑफिस में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) यानी रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल थे। शिकायत के आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 11 सितंबर, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच की अनुमति दी। इसके बाद उनके आय और संपत्ति के स्रोतों की विस्तृत जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि ललित कुमार की कुल कमाई 93.26 लाख

रुपए थी, जबकि चल और अचल संपत्तियों की खरीद, रखरखाव और अन्य मदों पर उनका कुल खर्च 1.61 करोड़ रुपये पाया गया। इस तरह उन्होंने अपनी वैध कमाई से 68.66 लाख रुपये, यानी करीब 73.6 प्रतिशत अधिक खर्च किया। जांच एजेंसी के अनुसार, इस अतिरिक्त खर्च और संपत्ति के संबंध में ललित कुमार कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसके बाद उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

शहीद पथ पर अमूल दूध से भरा ट्रक पलटा, टायर फटने से हुआ हादसा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बुधवार शाम शहीद पथ स्थित सेक्टर-8 अंडरपास के ऊपर अमूल दूध से भरा एक ट्रक पलट गया। यह हादसा अचानक टायर फटने से हुआ, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया। दुर्घटना में ट्रक में लदे दूध के कई पैकेट फटकर सड़क पर बिखर गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, सीतापुर के निमसार थाना क्षेत्र के रामपुर ठेवता निवासी करण नामक चालक ट्रक (यूपी-32 टीटी-4874) चला रहा था। ट्रक अहिमामऊ की ओर से एयरपोर्ट की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान अचानक टायर फटने से चालक अपना संतुलन खो बैठा और वाहन पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पीजीआई और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को हटवाया और सड़क पर बिखरे दूध के पैकेट साफ करवाए। इसके बाद शहीद पथ पर यातायात को सामान्य किया गया। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

'नगर निगम अफसरों की लापरवाही से गई लालाराम की जान'

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में अंडरग्राउंड नाले की सफाई के दौरान हुई कर्मचारी की मौत के मामले में नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि नालों की सफाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। सिर्फ कागजों में गुणवत्तापरख काम कर रहे हैं। ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। नालों की सफाई के दौरान नगर निगम की तरफ सुरक्षा मानकों को लेकर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। सबकुछ ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लालाराम को भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंडरग्राउंड नाले में उतारा गया था। उसकी मौत के बाद भी शहर में बिना सुरक्षा उपकरण के नालों की सफाई कराई जा रही है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार, मैनहोल या सीवर की सफाई से पहले मानक प्रक्रिया के तहत परीक्षण टेस्टिंग की तैयारी के लिए कम से कम तीन मैनहोल के ढक्कन खोले जाते हैं। इसके बाद लाइन में ताजी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक सक्शन पंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लाइन के अंदर प्रवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके ऑक्सीजन की रीडिंग ली जाती है। इसके साथ ही यातायात में व्यवधान कम हो इस लिए रात में काम को करने की सलाह है। हालांकि, यह काम व्यस्त चौराहे पर दोपहर के समय में किया गया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में बताए गए करीब सभी नियमों का चिनहट तिराहे पर नाला सफाई के दौरान उल्लंघन किया गया। बावजूद इसके अधिकारी सिर्फ कांट्रैक्ट नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।

टीबी मुक्त भारत की दिशा में उन्नाव का अहम कदम मरीजों को पौष्टिक आहार वितरित

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी वितरण कार्यक्रम का सुमेरपुर में शुभारंभ हुआ। बुधवार को ब्लॉक सभागार में तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश स्तर से किए गए कार्यों के शुभारंभ का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं, 1.10 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर अखिलेश कुमार वर्मा रहे। मुख्य अतिथि योगेश बाजपेई ने अपने संबोधन में शिक्षा विभाग और शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को शिक्षकों के लिए अत्यंत लाभकारी पहल बताया।कार्यक्रम का संचालन अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि बीडीओ पंकज गौतम, जीआईसी प्रिंसिपल दिलीप भदोरिया, सुमेरपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप सिंह, एसबीआई रिजिनल बिजनेस ऑफिस उन्नाव के मुख्य प्रबंधक नदीम हुसैन,

चिकित्साधिकारी वी पी सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ सुमेरपुर अध्यक्ष विनोद सिंह एवं बीघापुर अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, संघर्ष समिति अध्यक्ष देश दीपक पाण्डेय, एसबीआई शाखा प्रबंधक पाटन अजय कुमार, एसबीआई बीघापुर शाखा सह प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह चंदेल समेत कई अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

उन्नाव में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई। यह पहल इंडागों फूड प्राइवेट लिमिटेड, उन्नाव के सौजन्य से जिला क्षय रोग केंद्र (डीटीसी) और बिछिया टीबी यूनिट पर पंजीकृत मरीजों के लिए की गई। वितरित की गई पोषण पोटली में गुड़, चना, सत्तू, मूंगफली, सोयाबीन बड़ी और कॉर्नफ्लेक्स जैसी पोषक खाद्य सामग्री शामिल थी। इसका उद्देश्य टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीबी के उपचार के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक आहार भी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जनसहयोग के माध्यम से समय-समय पर मरीजों को पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से टीबी के प्रति जागरूक रहने, समय पर जांच कराने और उपचार को बीच में न छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे की धंसी साइड

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुभारंभ को जहां आज से महज सात दिन शेष हैं। वहीं इस एक्सप्रेसवे की व्यवस्था को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने काम शुरू कर दिया गया है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तरह इस एक्सप्रेसवे की फेंसिंग सुरक्षा जालियों आदि को काटकर ग्रामीण एक्सप्रेसवे पर जाने का अवैध रास्ता बना रहे हैं। सामान्य तौर पर बिना तय रास्ते के 30 फीट ऊंचे एक्सप्रेसवे पर ऐसे पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए सपोर्ट में पड़ी मिट्टी को भी ग्रामीणों पर खोदे जाने का आरोप एनएचएआइ की ओर से लग रहा है। एनएचएआइ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर ग्रामीणों पर कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने की भी तैयारी कर ली है। मानसून भले ही सक्रिय है, लेकिन जनपद में अभी तक ऐसी बरसात नहीं हुई कि बड़े व मजबूत निर्माण ढहने बहने लगें। कम बरसात के बीच गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के साइड सपोर्ट में किए गए काम टूटने, फटने व बहने लगे हैं। इनमें सपोर्ट में लगाई गई मिट्टी कई स्थानों पर बह गई है। वहीं जहां मिट्टी बही है वहां बड़े गड्ढे भी नजर आ रहे हैं।

उन्नाव में 11वां जय घुसेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में 11वें जय घुसेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट के सातवें दिन नागेश्वर इलेवन ने बेहटा इलेवन को 3 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला था, जिसमें भूरा के हरफनमौला प्रदर्शन ने नागेश्वर इलेवन को जीत दिलाई। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी नागेश्वर इलेवन ने शुरुआत से ही बेहटा टीम पर दबाव बनाए रखा। बेहटा के बल्लेबाज दीपक ने 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी करने में विफल रहे। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण बेहटा की पूरी टीम निर्धारित 12 ओवरों में 108 रन ही बना सकी। 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नागेश्वर इलेवन की टीम ने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। टीम ने 11.2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। नागेश्वर इलेवन की जीत के नायक भूरा रहे। उन्होंने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 30 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के दौरान मैदान पर दर्शकों का भारी उत्साह देखने को मिला। हजारों क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट में लगातार रोमांचक मुकाबलों के चलते दर्शकों की संख्या और उत्साह दोनों में बढ़ोतरी हो रही है।

उन्नाव में 14 पुलिसकर्मियों के तबादले, एसपी ने जारी किए आदेश

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 14 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। सभी संबंधित प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर उन्हें नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। जारी आदेश के अनुसार, महिला कांस्टेबल शालिनी शुक्ला को पुलिस लाइन से मानवाधिकार सेल भेजा गया है। नेहा शुक्ला को थाना मौरावां से थाना सोहरामऊ, शिखा सिंगर को थाना दही से थाना पुरवा, सुधा गोरखवी को थाना दही से थाना मौरावां और प्रिया भदौरिया को थाना पुरवा से थाना दही स्थानांतरित किया गया है। पुरुष पुलिसकर्मियों में, हेड कांस्टेबल हरिसिंह सिंह को पीआरवी सीयूजी बांगरमऊ से पीआरवी सीयूजी बीघापुर भेजा गया है। अरविंद कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना बिहार, कांस्टेबल अभय सिंह को परिवहन शाखा पुलिस लाइन से स्वाट टीम, मनीष केशर को थाना दही से थाना सफीपुर तथा प्रदीप कुमार को थाना एफ-84 से परिवहन शाखा पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। इसी क्रम में कांस्टेबल ओम नारायण सिंह को पुलिस लाइन से थाना दही, अर्पित चौधरी को पुलिस लाइन से थाना गंगाघाट, अंकिता चौधरी को थाना बांगरमऊ से थाना एफ-84 और महिला कांस्टेबल बेबी यादव को शाखा डीसीआरबी से थाना दही भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों को शीघ्र कार्यमुक्त कर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। एसपी ने बताया कि यह प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया एक नियमित स्थानांतरण है। इसका उद्देश्य विभिन्न इकाइयों और थानों में कार्य व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाना है।

उन्नाव जिला अस्पताल में हंगामा, महिला ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिला अस्पताल में एक महिला ने अपने बीमार बच्चे के इलाज में लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है। हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो में महिला खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताती है। उसका आरोप है कि उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉ. महेंद्र और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने उसकी बात नहीं सुनी। महिला ने दावा किया कि वह काफी देर से बच्चे को दिखाने की गुहार लगा रही थी, पर किसी ने जांच नहीं की। महिला ने डॉक्टर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। उसने कहा कि डॉक्टर ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और मरीज पर ध्यान नहीं दिया। महिला ने चेतावनी दी कि यदि उसके बच्चे को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वीडियो में कुछ अस्पतालकर्मी और अन्य लोग महिला के आरोपों का खंडन करते दिखे। एक स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि मरीज को देखा गया था और अस्पताल में अन्य गंभीर मरीज भी थे, जिनका इलाज चल रहा था। इस दौरान अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। वीडियो के अंत में डॉक्टर भी अपने मोबाइल फोन से घटना रिकॉर्ड करते नजर आते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों के उपचार पर सवाल उठने लगे हैं। सीएमओ डॉ. अजय शर्मा ने कहा है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

व्यक्तित्व निर्माण से होगा राष्ट्र निर्माण, भारत बनेगा पुनः विश्व गुरू: अनिल

उन्नाव में कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) पर स्थित गदनखेड़ा ओवरब्रिज की सड़क महज दो साल में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। पुल के डेक पर कई स्थानों पर ऊपरी परत उखड़ने से लोहे के गर्डर दिखने लगे हैं। इस कारण कार्यदायी संस्था ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और बुधवार को ओवरब्रिज की एक लेन पर यातायात रोक दिया गया। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए ओवरब्रिज की एक लेन को बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरी लेन से वाहनों का आवागमन जारी है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है। सड़क की ऊपरी परत कई जगहों से उखड़ गई है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर-लखनऊ हाईवे के विशेष मरम्मतीकरण पर लगभग 92 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। गदनखेड़ा चौराहे पर बने 1640 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के निर्माण पर करीब 64 करोड़ रुपये की लागत आई थी। इस परियोजना का ठेका वर्ष 2021 में दिया गया था और ओवरब्रिज को वर्ष 2024 में यातायात के लिए खोला गया था। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने इतनी जल्दी सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बने पुल की सड़क का इतनी कम अवधि में खराब होना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाता है। पुल की उखड़ी हुई सड़क वायरल वीडियो और तस्वीरों में भी स्पष्ट दिख रही है। जानकारी मिलने पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू कराया। हालांकि, संबंधित विभाग की ओर से अभी तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्षति सामान्य घिसाव के कारण हुई है या निर्माण संबंधी किसी तकनीकी खामी की वजह से। फिलहाल कार्यदायी संस्था का कहना है कि प्रभावित हिस्से की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है ताकि यातायात सामान्य रूप से संचालित हो सके। वहीं स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन एचडी अहिरवार ने बताया कि कार्यदायी संस्था से इस सम्बंध में सवाल जवाब लेकर जांच की जाएगी।

अयोध्या की जमीन पर अमिताभ बच्चन का बड़ा दांव

एक के बाद एक खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी

'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' (HoABL) के फाउंडर और चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने एक निजी चैनल से से बातचीत में बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें खुद फोन किया था। बातचीत के दौरान बिग बी ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश से हैं और अयोध्या में जमीन खरीदना चाहते हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले कुछ सालों से अयोध्या में लगातार रियल एस्टेट निवेश को लेकर चर्चा में हैं। राम मंदिर निर्माण और उसके बाद शहर में बढ़ती निवेश संभावनाओं के बीच बिग बी ने यहां एक के बाद एक कई जमीनों में निवेश किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रियल एस्टेट कारोबारी अभिनंदन लोढ़ा ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसके बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया कि आखिर अयोध्या में बिग बी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है। 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' (HoABL) के फाउंडर और चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने एक निजी चैनल से से बातचीत में बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें खुद फोन किया था। बातचीत के दौरान बिग बी ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश से हैं और अयोध्या में जमीन खरीदना चाहते हैं। लोढ़ा के मुताबिक, कीमत बताने के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन ने करीब 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच अयोध्या में निवेश की शुरुआत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन अयोध्या में जमीन खरीदने वाले शुरुआती बड़े फिल्मी सितारों में शामिल हैं। उन्होंने साल 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले 'द सरयू' परियोजना में करीब 10,000 वर्ग फुट का पहला प्लॉट खरीदा था। इस जमीन की कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसी खरीद के साथ अयोध्या में उनके निवेश का सफर शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद 16 जनवरी 2025 को अमिताभ बच्चन ने हवेली अवध नाम की रिहायशी परियोजना में एक और प्लॉट खरीदा। इस सौदे की अनुमानित कीमत 4.54 करोड़ रुपये बताई गई थी। यह खरीद उनके अयोध्या पोर्टफोलियो का दूसरा बड़ा निजी निवेश मानी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो, मई 2025 में बिग बी ने करीब 25,000 वर्ग फुट का एक और भूखंड खरीदा। यह जमीन भी 'द सरयू' परियोजना के पास स्थित है और इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई गई। इस निवेश के साथ अयोध्या में उनकी लग्जरी रियल एस्टेट हिस्सेदारी और मजबूत हो गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमिताभ बच्चन ने एक और महत्वपूर्ण जमीन खरीदी, जिसे हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत कराया गया। यह भूखंड करीब 54,454 वर्ग फुट क्षेत्रफल का है और राम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बच्चन परिवार से जुड़ा अयोध्या का दूसरा बड़ा निवेश माना जाता है। इसके बाद मार्च 2026 में अमिताभ बच्चन ने अयोध्या के तिहुरा माझा इलाके में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। इस सौदे की कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई गई।

चंपत राय ने पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व प्रमुख चंपत राय ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी से जुड़े विवाद पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। राम भक्तों को लिखे एक खुले पत्र में, राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वे विस्तार से जवाब देंगे। X पर शेयर किए गए पत्र में राय ने कहा कि मंदिर के दान-पात्रों से दान की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर 6 जून, 2026 से चर्चा चल रही है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस मामले से जुड़े कई आरोपों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक जानबूझकर चुप्पी साधे रखी थी। SIT जांच का ज़िक्र करते हुए राय ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए तैयार की गई एक शुरुआती रिपोर्ट, जिसे बेहद गोपनीय दस्तावेज़ होना चाहिए था, अब सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने कहा कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वे हर आरोप का बिंदुवार जवाब देंगे और उन्हें भरोसा है कि जांच पूरी होने पर सच सामने आ जाएगा। अपनी ईमानदारी का बचाव करते हुए राय ने कहा कि उन्हें अक्टूबर 1991 में संगठन ने अयोध्या भेजा था और वे पिछले 45 वर्षों से पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी उन्होंने काम किया है, उनका सार्वजनिक जीवन हमेशा एक खुली किताब की तरह रहा है और उन्होंने सभी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया।

अधिकारी के पास से कैश, सोना-चांदी बरामद

उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापे में विजिलेंस की टीम को सोने-चांदी और बेनामी संपत्तियों का भारी जखीरा हाथ लगा है। इतनी बड़ी बरामदगी ने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। विजिलेंस विभाग के मुताबिक ललित कुमार तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जनपद आगरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके ठिकानों पर विभाग की ओर से 7 और 8 जुलाई को सर्च की कार्रवाई की गई। ललित कुमार के ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कीमती आभूषण और नकदी बरामद हुई है। तलाशी के दौरान टीम को लगभग 9 किलोग्राम सोना, 13 किलोग्राम चांदी और अन्य बहुमूल्य आभूषण मिले हैं। बरामद किए गए इस सोने-चांदी की बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। सोने-चांदी के अलावा, आरोपी अधिकारी के पास से लखनऊ और नोएडा में फ्लैट्स और जमीनों के भारी-भरकम निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि ललित कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। वे सर्विस से रिटायर होने के बाद चंद्रलोक कॉलोनी सेक्टर-ई, अलीगंज में रहते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज मुकदमे के बाद कोर्ट की ओर से आरोपी की आवास पर सर्च की का वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर छापे की कार्रवाई की गई। सर्च के दौरान आरोपी के मकान में भारी मात्रा में कैश, सोने और चांदी के बिस्किट, हीरे, बेशकीमती आभूषण आदि बरामद किए गए।

बरेली में शिक्षिका ने SSP से मांगी सुरक्षा

"मेरे पति को मेरे सामने दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया, अब उसी हत्या के मुकदमे में गवाही देने की वजह से मुझे भी मारने की साजिश रची जा रही है। मैं बहुत डरी हुई हूं, मुझे बचा लीजिए।" यह दर्द और खौफ बरेली की रहने वाली शिक्षिका संगीता गंगवार का है। अपनी जान खतरे में देख उन्होंने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अनुराग आर्य को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है। संगीता गंगवार ने बताया कि साल 2021 में उनके देवर विनोद गंगवार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। उसके पति पुष्पेंद्र गंगवार अदालत में भाई की हत्या की मजबूती से पैरवी कर रहे थे। इसके बाद साल 2024 में उनके पति पुष्पेंद्र गंगवार को भी बीच चौराहे पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि वह अपने पति की हत्या की चश्मदीद गवाह हैं और अदालत में उनकी गवाही भी पूरी हो चुकी है। संगीता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति की हत्या एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी। उनके अनुसार मुख्य आरोपी पूरन लाल ने हत्या से पहले ही खुद को एक अन्य मामले में सरेंडर कर दिया था और जेल चला गया था ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरोप है कि उसने जेल के अंदर से ही पूरे हत्याकांड की साजिश रची और अपने गुर्गों के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलाया। संगीता का कहना है कि उनके पति की हत्या के मामले में 15 आरोपी नामजद हैं। इनमें से कुछ आरोपी अब जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। यही लोग अब उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि उन्हें जेल तो जाना ही है इसलिए उससे पहले वे संगीता को भी खत्म कर देंगे जिससे मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई न बचे। संगीता ने आरोप लगाया है कि हाल ही में जमानत पर बाहर आए संतोष समेत कई लोग उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने पूरन लाल, संतोष, गुड्डू, प्रेम, दुर्वेश, सुरेंद्र, महेंद्र, और कान्हा के भाई महेश कुमार, राकेश, रमेश, वीरेश, यशपाल, गजनहेरा निवासी सोमपाल और मुरारपुर के कोटेदार रामप्रकाश का नाम लिया है। उनका कहना है कि ये सभी मिलकर उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। शिक्षिका का कहना है कि पति की हत्या का मुकदमा अब अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही अदालत का फैसला आ सकता है। इसी वजह से सभी आरोपी घबराए हुए हैं और गवाह को जान से मारकर पूरे मामले को कमजोर करना चाहते हैं। संगीता ने दावा किया है कि उनके पास हत्या की साजिश से जुड़े पुख्ता सबूत भी हैं जिन्हें वह पुलिस और जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार हैं। आरोपियों के खौफ के कारण इलाके का कोई भी व्यक्ति खुलकर गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।